



प्रलिमिंस फैक्ट : 30 अप्रैल, 2021

- [कृषि अवसंरचना कोष](#)

कृषि अवसंरचना कोष

Agriculture Infrastructure Fund

[कृषि अवसंरचना कोष](#) ने आठ हजार करोड़ रुपए का आँकड़ा पार कर लिया है। यह नविश कई कृषि परियोजनाओं को बढ़ावा देगा, जो क पूरे देश में किसानों के लिये लाभकारी सिद्ध होगा।

प्रमुख बडि:

यह एक [केंद्रीय कषेत्तरक योजना](#) है।

लक्ष्य:

- फसल-कटाई के बाद की बुनियादी सुविधाओं और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों से संबंधित व्यवहार्य परियोजनाओं में नविश हेतु मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करना।
- इस धनराशिका प्रयोग केंद्र/राज्य/स्थानीय निकायों द्वारा प्रायोजित फसल एकत्रीकरण के लिये पीपीपी परियोजनाओं के अलावा कोल्ड स्टोर और चेन, वेयरहाउसिंग, ग्रेडिंग और पैकेजिंग यूनिट, ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े ई-मार्केटिंग पॉइंट आदि की स्थापना हेतु किया जाएगा।

अवधि: वित्तीय वर्ष 2020 से 2029।

वशिषताएँ:

- **योग्य लाभधारक:**
 - इस कोष से किसानों, किसान उत्पादक संगठनों, PACS, वपिन सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों, संयुक्त देयता समूहों (JLGs), बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, कृषि-उद्यमी, स्टार्ट-अप और केंद्रीय/ राज्य एजेंसी या स्थानीय प्रायोजित सार्वजनिक-नज्दी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं को लाभ मिलेगा।
- **वित्तीय सहायता: बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा पात्र लाभार्थियों को ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए तक प्रदान किया जाएगा।**
 - पुनर्भुगतान के लिये अधस्थगन अवधि न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 2 वर्ष हो सकती है।
- **इंटरैस्ट सबवेंशन: 2 करोड़ रुपए की सीमा तक के ऋण के लिये 3% प्रतिवर्ष का इंटरैस्ट सबवेंशन होगा। यह अधिकतम सात वर्षों के लिये उपलब्ध होगा।**
- **CGTMSE योजना: 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिये 'क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज' (CGTMSE) योजना के तहत पात्र उधारकर्ताओं के लिये एक क्रेडिट गारंटी कवरेज उपलब्ध होगा।**

केंद्रीय कषेत्तरक योजना:

- ये योजनाएँ केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित होती हैं।
- इन्हें केंद्र सरकार की मशीनरी द्वारा लागू किया जाता है।
- मुख्य रूप से संघ सूची के वषियों से संबंधित।
- जैसे: भारतनेट, नमामि गंगे-राष्ट्रीय गंगा योजना आदि।

